

652वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 जून 2023

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 652वीं बैठक दिनांक 14/06/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :-

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रुबीना चौधरी, सदस्य ।
3. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
4. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
5. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
6. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. **प्रकरण क्रमांक 9026/2022 - मेसर्स के.पी. अवस्थी, पार्टनर, बिचपुरा मेटल क्वेरी, बिचपुरा बरही, जिला कटनी (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 1038/2, 1037/1, 1037/2, 1037/3, 1033/1 रकबा 2.63 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन - 60,209 मी.³ प्रतिवर्ष ग्राम बिचपुरा बरही, तहसील बरही जिला कटनी (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आन लाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 1038/2, 1037/1, 1037/2, 1037/3, 1033/1 रकबा 2.63 हेक्टेयर, ग्राम बिचपुरा बरही, तहसील बरही जिला कटनी (म.प्र.) पर स्थित है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 556वीं दिनांक 02/03/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

प्रकरण आज सेक की 652वीं बैठक दिनांक 14/06/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

2. **Case No 9743/2023 Shri Neeaj Mangal, Owner, R/o Lehroni, Tehsil-Karahal, District-Sheopur (MP) Prior Environment Clearance for Karathal Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (5088 Cum per annum) (Khasra No. 1412/1/1 Govt.), Village-Karathal, Tehsil-Karahal, District-Sheopur (MP)**

652वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 जून 2023

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1412/1/1 Govt.), Village- Karathal, Tehsil- Karahal, District-Sheopur (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 21/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री नीरज मंगल (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 866 दिनांक 31/01/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है। अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रकरण के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से समिति ने पाया कि पी-2 फार्म अनुसार आवंटित खसरा लगभग 23.0 हे. का है जिसमें आई.टी.आई. हेतु भवन निर्माण, खेल के मैदान का निर्माण, ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण तथा सांख्यिकी भवन निर्माण इत्यादि कार्य किये जाना प्रस्तावित किये गये हैं जो संवेदनशील प्रकृति के हैं तथा इन्हीं के पास पत्थर की एक खदान स्वीकृत की गई है जिसमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है। अतः समिति की अनुशंसा है कि संबंधित कलेक्टर उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में पुर्नविचार कर इस स्थल पर खदान स्वीकृति के संबंध में अपने मत से समिति को अवगत कराये तथा यह भी स्पष्ट करे कि प्रस्तावित आई.टी.आई. भवन, खेल का मैदान, ट्रेनिंग सेंटर तथा सांख्यिकी भवन की दूरी आवंटित खदान से कितनी है। संभवतः यह क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र के दायरे में आता है अतः समिति की अनुशंसा है कि संबंधित कलेक्टर यह सुनिश्चित करले कि यह क्षेत्र पेसा एक्ट, 1996 में अधिसूचित क्षेत्र या नहीं एवं यदि यह क्षेत्र पेसा एक्ट 1996 में अधिसूचित है तो क्या उसमें निहित प्रावधानों के अनुरूप यह स्वीकृति प्रदान की गई है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 29/5/23 को अपलोड कर दी गई है, जो दिनांक 14/06/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री महावीर सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि माईनिंग प्लान नॉन ब्लास्टिंग पर आधारित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि उक्त ग्राम पेसा (Panchayat (Extension to Scheduled Areas) के अंतर्गत आता है, अतः गांव के मजरे या टोला का अनापत्ति प्रमाण पेसा एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 5088 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 10.88 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 01.17 लाख प्रति वर्ष।

652वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 जून 2023

3. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियां	राशि रु.
1. कराहल आंगनवाड़ी में पुताई एवं मरम्मत एव पेंटिंग का कार्य किया जाएगा।	1,20,000/-
2. कराहल आंगनवाड़ी में बच्चों को खिलौने दिये जाएंगे।	

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1.	बैरियर जोन	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, सीताफल, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	400
2.	परिवहन मार्ग (पौधों की न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां पूर्ण सुरक्षा के साथ	300
	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवल, अमरुद, मुनगा, पपीता, निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1700
योग			2400

3. **Case No 9934/2023 Shri Neeraj Pratap Singh, Onwer, R/o Jaswantpura (Tamgarh), Tehsil-Gunnor, District-Panna (MP)-488001, Prior Environment Clearance for Atarhai Flagstone & M-Sand Quarry in an area of 1.80 ha. (M-Sand-12000, Flagstone-2700 cum per annum) (Khasra No. 3838), Village-Atarhai, Tehsil-Shahnagar, District-Panna (MP)**

This is case of Flagstone & M-Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 3838), Village-Atarhai, Tehsil-Shahnagar, District-Panna (MP) 1.80 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 14/06/23 को परियोजना प्रस्तावक नीरज प्रताप सिंह ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, मेसर्स अमलतास इंवायरो इण्डस्ट्रीयल कंसलटेंट, एलएलपी, गुरुग्राम (हरियाणा) उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि उनके इस प्रकरण में पर्यावरणीय सलाहकार मेसर्स अमलतास इंवायरो इण्डस्ट्रीयल कंसलटेंट, एलएलपी, गुरुग्राम (हरियाणा) के स्थान पर मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसलटेंसी, नोएडा, उ.प्र. की सेवाये ली

652वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 जून 2023

जा रही है जिसके संबंध में संबंधित दस्तावेज सिया/सेक को मेल भी किया गया है और प्रस्तुतीकरण में भी दिया है। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1651 दिनांक 21/11/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माईन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि डी.एस.आर. के कोआर्डिनेट एवं माईनिंग प्लान के कोआर्डिनेट अलग-अलग थे, खनिज अधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक 467 दिनांक 13/4/23 के द्वारा पुनरीक्षित कोआर्डिनेट प्रस्तुत किये गये हैं। आवंटित खदान का दक्षिण-पूर्व दिशा में लगभग 1.0 किलोमीटर से अधिक दूरी पर जल रोकने की संरचना है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि फ्लेग स्टोन से एम.सेंड निर्मित की जावेगी परन्तु इस हेतु एम.सेंड बनाने का प्रोसेस एवं स्लरी मैनेजमेंट प्लान नहीं प्रस्तुत किया गया अतः एम.सेंड बनाने का प्रोसेस एवं स्लरी मैनेजमेंट प्लान करने के पश्चात् आपके प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

4. Case No 9782/2023 Shri Mahavir Singh, Owner, R/o Village-Girgoni, Tehsil-Morena Hal, District-Morena (MP)-476444, Prior Environment Clearance for Girgoni Soil Quarry in an area of 1.00 ha. (2100 Cum per annum) (Khasra No. 365, 574 Private) Village-Girgoni, Tehsil-Morena Hal Bamore, District-Morena (MP)

This is case of Soil Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 365, 574 Private) Village-Girgoni, Tehsil-Morena Hal Bamore, District-Morena (MP) 1.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 06/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री महावीर सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 1230 दिनांक 24/11/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नहीं दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान दो भागों में आवंटित है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह खदान निजी भूमि पर आवंटित है तथा 01 हे. का न्यूनतम क्षेत्र पूर्ण करने बावत् खदान 02 भागों में आवंटित है। परियोजना प्रस्तावक ने यह भी बताया कि दोनों क्षेत्र के बीच में क्लिंन स्थापित है, जिसमें इस खदान से निकलने वाली मिट्टी द्वारा निर्मित ईंटों को पकाया जायेगा। समिति ने पाया कि आवंटित खनन

652वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 जून 2023

क्षेत्र के एक भाग के पूर्वी दिशा में 10 मीटर की दूरी कच्चा रोड़ तथा दूसरे भाग के उत्तर दिशा में 320 मीटर पर आबादी है, जिस हेतु परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् मिट्टी का है, जिसमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है तथा खनन् की अधिकतम गहराई 02 मीटर होगी, जो मैनुअली किया जावेगा । उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज क्र०. 21 एवं सरल क्रमांक 36 पर दर्ज है किंतु जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में को-आर्डिनेट नहीं दिए गए हैं, अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश-देशांश के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :-

1. स्थापित क्लिन में कौन सा ईंधन उपयोग में लाया जायेगा ।
2. प्रस्तावित ईंधन का सोर्स क्या है ।
3. ईंधन के जलाने से जो राख उत्पन्न होगी उसका निष्पादन कैसे किया जायेगा ।
4. ईट बनाने के दौरान उपयोग में आने वाला पानी कहां से प्राप्त किया जायेगा ।
5. खनन् की गहराई 2.5 मीटर हेतु स्पष्टीकरण ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 29/4/23 को अपलोड कर दी गई है, जो दिनांक 14/06/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री महावीर सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता मिट्टी – 2100 मी³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 07.67 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 01.19 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.54 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियां	राशि रु.
ग्राम गिरगोनि के आँगन बाड़ी की मरम्मत और पुताई का कार्य किया जायेगा	54,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
-------	------------------	---------------------	------------------------

652वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 जून 2023

1.	बैरियर जोन	सीताफल, आवलॉ, अमरुद, ग्राफिटिंग मुनगा, पपीता, निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	300
2.	परिवहन मार्ग (पौधों की न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
3.	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलॉ, अमरुद, ग्राफिटिंग मुनगा, पपीता, निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	700
योग			1200

5. Case No 9939/2023 Shri Hajri Ajnar, Lease Owner, R/o Village- Morasa, Tehsil- Jobat, District-Alirajpur (MP)- 457990, Prior Environment Clearance for Morasa Crusher Stone Deposit in an area of 0.440 ha. (4850 cum per annum) (Khasra No. 909), Village- Morasa, Tehsil- Jobat, District- Alirajpur (MP)

This is case of Stone Deposit. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 909), Village- Morasa, Tehsil- Jobat, District- Alirajpur (MP) 0.440 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 16/06/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री तारा अजनार ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री मुजम्मिल खान, (ऑनलाईन) मेसर्स इन-सीटू इन्वायरो केयर, भोपाल उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल पत्र क्रमांक 271 दिनांक 17/02/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 1.44 हे. है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माईन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के पश्चिम दिशा में 106 मीटर पर एवं पूर्व दिशा में 171 मीटर पर नदी स्थित है एवं खदान क्षेत्र में कुछ पेड़ दिख रहे हैं। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि इस खदान का डिया से पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृत प्राप्त है। यह खदान 0.440 हे. की है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह खदान 2006 के पहले का प्रकरण है वर्ष 2017 में नवीनीकरण हो चुका है जिसमें 1.0 हे. क्षेत्र की अनिवार्यता लागू नहीं है।

652वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 जून 2023

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-40 के सरल क्रमांक 4 पर दर्ज है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि प्रश्नाधीन खदान को पूर्व में डिया से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हुई है अतः डिया की अन्य शर्तों के साथ फेंसिंग के फोटोग्राफ, मिट्टी के कटाव को बचाने के लिये ट्रेंच बनाने का प्रस्ताव, वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. संबंधी शर्तों का पूर्णतः पालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करें।

6. Case No 9937/2023 Shri Ram Garg, Owner, R/o- B-08, Marga Residency, Heavy Machinery Tin Shed Ke Samne, Bypass Road, District-Sheopur (MP)- 476337, Prior Environment Clearance for Kilgaonri Stone Quarry in an area of 1.7760 ha. (15200 cum per annum) (Khasra No. 54/7), Village-Kilgaonri, Tehsil-Sheopur, District-Sheopur (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 54/7), Village-Kilgaonri, Tehsil-Sheopur, District-Sheopur (MP) 1.7760 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 14/06/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राम गर्ग और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल पत्र क्रमांक 270 दिनांक 17/02/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर 1.600 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माईन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के दक्षिण पश्चिम दिशा में 383 मीटर पर एवं दक्षिण-पूर्व दिशा में 270 मीटर पर केनाल है एवं दक्षिण-पूर्व में 11 मीटर पर मकान है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह मकान पास की खदान का ऑफिस/आश्रय स्थल है, खदान में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि दक्षिण-पूर्व में 11 मीटर पर मकान स्थित होने के संबंधित खनिज अधिकारी से इस संबंध पुष्टि करवाये पास की खदान का ऑफिस/आश्रय स्थल है, तत्पश्चात् प्रकरण पर विचार किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

5. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 15,200 मी³ प्रति वर्ष।

652वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 जून 2023

6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 11.68 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 01.22 लाख प्रति वर्ष ।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियां	राशि रु.
किलगवाड़ी ग्राम के प्राथमिक शाला हेतु बच्चों के लिए 38 कुर्सी टेबल के सेट दिए जायेंगे	75,000
1 कंप्यूटर एवं ब्लैक – वाइट प्रिंटर टेबल चेयर सेट के साथ दिया जाएगा	45,000
योग	1,20,000

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1.	बैरियर जोन	चिरोल , नीम , जंगल जलेबी , सीताफल, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	400
2.	परिवहन मार्ग (पौधों की न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर)	करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी , एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	300
3.	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलॉ, अमरुद, मुनगा, पपीता] निम्बू आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1500
योग			2200

7. Case No 9938/2023 Smt. Tara Ajnar, Lease Owner, R/o Village-Pratapfaliya, Tehsil- Jobat District-Alirajpur (MP)- 476337, Prior Environment Clearance for Pratapfaliya Crusher Stone Deposit in an area of 0.600 ha. (2425 cum per annum) (Khasra No. 244/1, 244/2), Village- Pratapfaliya, Tehsil- Jobat, District- Alirajpur (MP)

This is case of Stone Deposit. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 244/1, 244/2), Village- Pratapfaliya, Tehsil- Jobat, District- Alirajpur (MP) 0.600 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 16/06/23 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती तारा अजनार ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री मुजम्मिल खान, (ऑनलाईन) मेसर्स इन-सीटू इन्वायरो केयर, भोपाल

652वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 जून 2023

उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल पत्र क्रमांक 270 दिनांक 17/02/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 1.60 हे. है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माईन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के दक्षिण दिशा में 60 मीटर पर पक्का रोड है, उत्तर-पूर्व में 495 मीटर पर कंस्ट्रक्शन/स्ट्रेक्चर दिख रहा है एवं खदान क्षेत्र के अंदर केशर स्थापित है। विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-34 के सरल क्रमांक-5 पर दर्ज है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि इस खदान का डिया से पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृत प्राप्त है। यह खदान 0.600 हे. की है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह खदान नवीनीकरण की है जिसमें 1.0 हे. क्षेत्र की अनिवार्यता लागू नहीं है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रश्नाधीन खदान में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है परन्तु दूरी के संबंध में स्थानवार मापदंड छोड़ने के फलस्वरूप खनन योग्य क्षेत्र कम उपलब्ध होता है अतः उनके द्वारा नॉन ब्लास्टिंग का प्रस्तावित है। चूंकि खदान एरिया में केशर स्थापना प्रस्तावित है इसकी लोकेशन कहाँ होगी तथा दक्षिण दिशा में 60 मीटर की दूरी में पक्का रोड होने के कारण सेटबैक छोड़ा जाना प्रस्तावित है अतः इस संबंध में समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिया कि संबंधित खनिज अधिकारी से इस तथ्य की तकनीकी रूप से पुष्टी कराले कि नॉन ब्लास्टिंग के संबंध में स्थानवार मापदंड छोड़ने के फलस्वरूप इस खदान में खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध होगा अथवा नहीं।

8. Case No 9936/2023 Shri Anurag Solanki, Lessee, R/o- Ward No. 2, Khandwa Road Sanawad, District-Khargone (MP)-451111, Prior Environment Clearance for Gumthi Stone & M-sand in an area of 3.800 ha. (Stone – 8000 cum per annum & M-sand – 8000 cum per annum) (Khasra No. 101/1, 103/1, 104/1, 105/1), Village-Gumthi, Tehsil-Sanawad, District-Khargone (MP)

This is case of Stone & M-sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 101/1, 103/1, 104/1, 105/1), Village-Gumthi, Tehsil-Sanawad, District-Khargone (MP) 3.800 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 14/06/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री अनुराग सोलंकी ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राम राघव, मे0. ग्रीन सर्कल आई.एन.सी. बडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 64 दिनांक 13/04/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

652वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 जून 2023

खदान निजी/शासकीय भूमि पर आवंटित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर-पश्चिम दिशा में 40 मीटर पर पक्का रोड़ है, पश्चिम-पूर्व दिशा में 312 मीटर पर स्टॉप डेम, पश्चिम दिशा में 162 मीटर पर केनाल, खदान के उत्तर-पूर्वी दिशा से लगी हुआ प्राकृतिक नाला है जिसके संदर्भ परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि नाला के संरक्षण हेतु 50 मीटर का एवं 60 मीटर का पक्का रोड़ के संबंध में नॉन माईनिंग क्षेत्र दिखते हुए पुनरीक्षित सरफेस में पर सेटबेक प्रस्तुतीकरण के साथ दिया गया है । प्रश्नाधीन खदान में 07 पेड़ लगे दिख रहे हैं जिसमें से 03 पेड़ शासकीय भूमि पर हैं उन्हें काटा जाना प्रस्तावित है जिसके एवंज में 10 पेड़ अतिरिक्त लगाये जाने का प्रस्ताव है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन कार्य किया जावेगा जिसमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन ने पत्र क्रमांक 116 दिनांक 25/04/23 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त प्रकरण में संपूर्ण औपचारिकतायें पूर्ण होने के उपरांत उक्त पत्थर गिट्टी केशर उत्पनिपट्टा को आगामी डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 8,000 मी³ प्रति वर्ष एवं एम.सैंड – 8000 मी³ प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 16.46 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 02.28 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियां	राशि रु.
नजदीक स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ चिकित्सक के परामर्श से जरूरत के हिसाब से उपयोग हेतु सामग्री प्रदान की जावेगी ।	20,000
नजदीक स्थित ग्राम हीरापुर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में क्रिकेट किट का वितरण और एवं 2 कंप्यूटर एवं एक प्रिंटर उपलब्ध करवाए जावेंगे ।	60,000
कुल	80,000

652वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 जून 2023

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4600 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1.	बैरियर जोन	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- (शासकीय भूमि के बैरियर जोन में) कालासिरिस, सफेदसिरिस, खमेर, अंजड़, पीपल, सिस्सू, जंगल जलेबी, करंज, सीताफल, चिरोल (निजी भूमि के बैरियर जोन पर) आम, संतरा , जंगल जलेबी, मूंगा, जामुन, सीताफल, कटहल आदि।	1250
2.	परिवहन मार्ग (पौधों की न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- नीम, कदम्ब, जंगल जलेबी, खमेर, सिस्सू, पीपल, करंज आदि। पूर्ण सुरक्षा के साथ	100
3.	उत्खनिपट्टे के गैर-खनन क्षेत्र (4500 वर्ग मीटर) में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- कालासिरिस, सफेदसिरिस, अंजड़, खमेर, पीपल, सिस्सू , जंगल जलेबी, करंज , सीताफल, चिरोल, पाखड़, पीपल आदि।	1500
4.	ग्राम गुमटी के ग्रामीणों में पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- मूंगा, आम, संतरा, जामुन, सीताफल, कटहल, संतरा आदि।	1750
योग			4600

9. Case No 9302/2022 M/s Micro Minerals, R/o Gokul Dham Colony, Dist. Katni, MP - 483501 Prior Environment Clearance for Limestone and Dolomite Mine in an area of 5.470 ha. (Limestone - 24458 Tonne per annum, Dolomite - 5984 Tonne per annum) (Khasra No. 66, 67, 68, 69) Village - Baragaon, Tehsil - Barwara, Dist. Katni, (MP)

This is case of Limestone and Dolomite Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 66, 67, 68, 69) Village - Baragaon, Tehsil - Barwara, Dist. Katni, (MP) 5.470 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 594वीं दिनांक 21/09/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

652वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 जून 2023

आज दिनांक 14/06/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री राधाकृष्ण अग्रवाल (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए ।

खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान उत्तर-पूर्व दिशा में एक कच्चा रोड दिख रही है इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह खनिज परिवहन मार्ग है । प्रश्नाधीन खदान में 40 पेड़ लगे दिख रहे हैं जिसमें से 20 पेड़ काटा जाना प्रस्तावित है जिसके एवंज में 200 पेड़ अतिरिक्त लगाये जाने का प्रस्ताव है एवं जो 20 पेड़ बैरियर जोन में हैं उन्हें सुरक्षित रखे जायेगा । परियोजना प्रस्तावक ने प्रस्तुतीकरण दौरान बताया कि उनके द्वारा 200 पौधों का रोपण कर दिया है, समिति ने संज्ञान में लिया कि अभी पौधे लगाने का उपयुक्त समय नहीं क्योंकि दूरस्थ स्थानों में पानी की व्यवस्था नहीं पायेगी अतः परियोजना प्रस्तावक रोपण का जब समय हो जब ही पौधे लगाये, पौधे हमेशा 2.5 से 3.0 फिट लगाना उपयुक्त होता है । प्रस्तुतीकरण के दौरान आवेदित क्षेत्र के वायु गुणवत्ता के परिणाम (पी.एम. 2.5 माईक्रोन) आस-पास की गतिविधि को देखते हुए अधिक प्रतीत हो रही है अतः परियोजना प्रस्ताव संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संपर्क के भुगतान के आधार पर वायु गुणवत्ता को डाटा पुनः प्रस्तुत करें ।

10. Case No 9254/2022 Shri Rakesh Agrawal, Owner, G-I-1, Chouraha, Scheme No. 94, Dist. Indore, MP, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (50000 cum per annum) (Khasra No. 639, 645, 648) near Village - Khandwa, Tehsil - Pithampur, Dist. Dhar (M.P.)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 639, 645, 648) near Village - Khandwa, Tehsil - Pithampur, Dist. Dhar, (MP) 3.20 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 583वीं दिनांक 30/06/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है ।

प्रकरण आज सेक की 652वीं बैठक दिनांक 14/06/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे ।

652वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 जून 2023

11. Case No 9947/2023 Shri Om Prakash Rai, Owner, M/S Vijay & Company Private Limited, Rai Bhawan, Katni Road P.O.- Maihar, District-Satna (MP)-485771, Prior Environment Clearance for Bathia Stone Quarry in an area of 3.962 ha. (115026 Tonne per annum) (Khasra No. 904, 905), Village-Bathia, Tehsil-Maihar, District-Satna (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 904, 905), Village-Bathia, Tehsil-Maihar, District-Satna (MP) 3.962 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 14/06/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री ओमप्रकाश राय (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संजय सिंह, मेसर्स पी एंड एम साल्यूशन नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1155 दिनांक 06/06/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 07 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

खदान निजी भूमि पर आवंटित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के पश्चिम दिशा में 319 मीटर पर पक्का रोड़ एवं उत्तर-पश्चिम दिशा में 695 मीटर पर आबादी है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना ने पत्र क्रमांक 857 दिनांक 01/05/23 के द्वारा सूचित किया है कि उपरोक्त उत्खनिपट्टा में संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण (उत्खनिपट्टा संचालन) होने जाने उपरांत नवीन डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट में स्वीकृत उत्खनिपट्टा को शामिल किया जावेगा। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टैण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. खदान के प्रस्तुत माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के पश्चिम दिशा में 319 मीटर पर पक्का रोड़ है। अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. में प्रस्तुत की जाये।
2. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर

652वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 जून 2023

- उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
 4. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
 5. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

12. Case No 9942/2023 Shri Rajeev Rai, Owner, R/o 214, Chhaniya Jhansi Khas, Tehsil- Jhansi, District-Jhansi (UP)- 284002, Prior Environment Clearance for Jijora Stone Quarry in an area of 1.928 ha. (40000 cum per annum) (Khasra No. 679/2/1), Village- Jijora, Tehsil- Orchha, District-Niwari (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 679/2/1), Village- Jijora, Tehsil- Orchha, District-Niwari (MP) 1.928 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 14/06/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री ओमप्रकाश राय (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 602 दिनांक 06/12/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 06 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

खदान निजी भूमि पर आवंटित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के दक्षिण-पश्चिम दिशा में 205 मीटर पर नदी, दक्षिण-पूर्व दिशा में 44 मीटर पर आबादी है, इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुत करे तथा उत्तर-पूर्व भाग कुछ खुदा हुआ है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाड़ी ने पत्र क्रमांक 43 दिनांक 18/04/23 के द्वारा सूचित किया है कि उपरोक्त उत्खनिपट्टा में संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण (उत्खनिपट्टा संचालन) होने जाने के उपरांत नवीन डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट में स्वीकृत उत्खनिपट्टा को शामिल किया जावेगा।

समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306

652वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 जून 2023

दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. खदान के दक्षिण-पश्चिम दिशा में 205 मीटर पर नदी, दक्षिण-पूर्व दिशा में 44 मीटर पर आबादी है, इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुत करे ।
2. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
4. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

13. Case No 9941/2023 Shri Raj Kumar, Owner, R/o 175/5, Chhaniyapura, Jhansi, District-Jhansi (UP)- 284002, Prior Environment Clearance for Jijora Stone Quarry in an area of 1.20 ha. (25000 cum per annum) (Khasra No. 679/4/678), Village-Jajora, Tehsil- Orchha, District-Niwari (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 679/4/678), Village- Jajora, Tehsil- Orchha, District-Niwari (MP) 1.20 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 14/06/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री राज कुमार (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 517 दिनांक 21/10/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

652वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 जून 2023

खदान निजी भूमि पर आवंटित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के दक्षिण-पश्चिम दिशा में 106 मीटर पर नदी, उत्तर-पूर्व दिशा में 501 मीटर पर आबादी है, इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुत करे, खदान में कुछ पेड़ हैं एवं खदान का कुछ भाग आंशिक रूप से खुदा है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाड़ी ने पत्र क्रमांक 42 दिनांक 18/04/23 के द्वारा सूचित किया है कि उपरोक्त उत्खनिपट्टा में संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण (उत्खनिपट्टा संचालन) होने जाने के उपरांत नवीन डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट में स्वीकृत उत्खनिपट्टा को शामिल किया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. खदान के दक्षिण-पश्चिम दिशा में 106 मीटर पर नदी, उत्तर-पूर्व दिशा में 501 मीटर पर आबादी है, इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करे ।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊंचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
3. प्रश्नाधीन खदान का कुछ भाग आंशिक रूप से खुदा है इस संबंध में जिला खनिज अधिकारी से स्पष्ट अभिमत ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करे ।
4. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

14. Case No 9951/2023 Shri Vivek Dubey, Partner, M/s Stone Works Mining, R/o Ram Manohar Lohiya Ward, Nadipur, Infront of Pali Threshers, District-Katni (MP)-483501, Prior Environment Clearance for Malhan Dolomite Mine in an area of 3.42 ha. (51488 Tonne per annum) (Khasra No. 293, 294, 295), Village-Malhan, Tehsil-Badwara, District-Katni (MP)

This is case of Dolomite Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 293, 294, 295), Village-Malhan, Tehsil-Badwara, District-Katni (MP) 3.42 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

PP vide their e-mail requested that we have withdrawn the case no 9951/2023 as the name of project proponent was inadvertently written as Shri Vivek Dubey, Partner, M/s Stone Works Mining Private Limited instead of Shri Vivek Dubey, Partner, M/s D A Mines and Minerals. This happened due to the PAN card uploading of project proponent mistakenly. On notice, we immediately withdrew the case and re loaded the same case with the correct name of PP and registered as case No 9980/2023. Therefore, we kindly request you to consider file no. 9980/2023 instead of 9951/2023 as the project and data is the same in both projects. On notice, we immediately withdrew the case and re loaded the same case with the correct name of PP and registered as case No 9980/2023. The Committee after deliberation recommends accept the PP's request for withdraw the case.

15. Case No 9935/2023 Shri H.P. Rath, Vice President (Operations), M/s Macleods Pharmaceuticals Limited, R/o Plot No. 50 to 54A, Indore Special Economic Zone, Phase-II, Pithampur, District-Dhar (MP)-454775, Prior Environment Clearance for proposed expansion in existing manufacturing (formulation) plant at Plot No. M-50 to M54A, Indore SEZ, Phase-II, Pithampur, District-Dhar (MP)

This is case of Prior Environment Clearance for proposed expansion in existing manufacturing (formulation) plant at Plot No. M-50 to M54A, Indore SEZ, Phase-II, Pithampur, District-Dhar (MP).

The case was presented for ToR by the PP Shri H.P. Rath, Vice President (Operations), and their Environmental Consultant Mr. Shri Shubham Dubey, M/s. EnviSolve , Indore . During presentation, PP submittd that this is an existing unit and they are proposing expansion in existing manufacturing (formulation) plant at Plot No. M-50 to M54A, Indore SEZ, Phase-II, Pithampur, District-Dhar (MP).

652वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 जून 2023

Following details were furnished by PP during presentation:-

- M/s Macleods Pharmaceuticals Limited was established in 1989. MPL engaged in developing, manufacturing, and marketing a wide range of formulations across several major therapeutic areas including anti-infectives, cardiovascular, anti-diabetic, dermatology, and hormone treatment.
- MPL has wide experience in API development and analytical development.
- M/s Macleods Pharmaceuticals Limited is currently engaged in Formulation of capsules and tablets (Non-EC Product) at Plot No M-50 to M-54A, Indore Special Economic Zone, Phase-II, Pithampur Dist.-Dhar. Now Macleods Pharmaceuticals Limited has proposed to manufacture ***Oncology bulk drugs & Peptide based bulk drugs***, for which prior environment clearance has to be taken.
- The project falls under 5 (f) (ii) category B of the EIA Notification & its amendments issued by the Ministry of Environment & Forest vide S.O.1533 (E), dated September 2006, & its amendments.
- It is an expansion in the existing formulation plant, Public hearing is not required as industry falls in a government notified industrial area.
- The total land area of the project site is 114200 m². Plot No. M-50 to M-54A Indore Special Economic Zone, Phase-II, Pithampur Dist. Dhar The sufficient land is available for expansion in the existing plot.
- Total cost of the project after expansion will be 236 Cr.

S.No.	Products	Existing	Proposed Quantity/ Annum	Total quantity /Annum
1	1. Capsules (Existing) 2. Tablets (Existing) (Non-EC Products)	1. Capsules-50 Cr/Year 2. Tablets-144 Cr./Year	Nil	1. Capsules-50 Cr /Year 2. Tablets-144 Cr./Year
2	Oncology bulk drugs Products(Proposed)	Nil	2000 Kg/year	2000 Kg/year
3	Peptide based bulk drugs(Proposed)	Nil	65Kg/year	65 Kg/year

Details of Proposed Products

S. No.	Name	Annual Capacity
1	Semaglutide	35 Kg

652वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 जून 2023

2	Linalcotide	10Kg
3	Liraglutide	20Kg
Total Quantity		65 Kg

After presentation, committee decided to recommend standard TOR prescribed by MoEF&CC with following additional TOR and as per Annexure-D:

1. Being expansion, certified compliance report of previous EC/ CTO conditions from the competent authority shall be submitted and if previously EC is not obtained justified reason with credible proof shall be submitted with EIA report.
2. Carbon foot print analysis for existing production and proposed production shall be studied and discussed in EIA report.
3. Proposed future greenery more than 30% in the project area.
4. After 50 years incorporating all development work how much green area shall be designated/ proposed location –wise as green area discussed in EIA report.
5. All process details with mass balance shall be discussed in the EIA report.
6. PP should provide entire product mix in the EIA report.
7. Detailed plant layout on A3 size map.
8. All process details with mass balance (productwise) shall be discussed in the EIA report.
9. Landuse pattern obtained from competent authority shall be discussed in EIA report.
10. How project will become “Zero Liquid Discharge” shall be discussed in the EIA report with complete details of treatment scheme, their various details and odour nuisance.
11. Provision for compatible storage of raw materials and finish products shall be studied and discussed in the EIA report.
12. Worst case scenario w.r.t. waste water and hazardous waste should be submitted.
13. Details of solvents and their recovery plan should be discussed in the EIA report.
14. VOC should be monitored in the AAQ (if any).
15. All MSDS should be provided with the EIA report.
16. Industry has to comply with zero discharge for which necessary details should be provided in the EIA report.
17. Land use plans of the plant both existing land use as well as proposed land use and PP should assure that no existing green area shall be altered for which a written commitment be submitted with the EIA report.
18. Details of tree planted with names and number of their species (till date) with height shall be submitted with EIA report.

652वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 जून 2023

19. PP should explore possibility of using Biofuel based technology in boilers.
11. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CSR cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CSR cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
12. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
13. Safety measures proposed for hydrogenation process.

16. Case No 9943/2023 Shri Uma Dubey, R/o A-28, Shukhliya, Indore, District-Indore (MP)-452010, Prior Environment Clearance for Dhureri Stone Quarry in an area of 3.00 ha. (63127 cum per annum) (Stone – 25,251 cum per annum and M-Sand – 37,876 cum per annum) (Khasra No. 51/1/1/1), Village-Dhureri, Tehsil- Depalpur, District-Indore (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 51/1/1/1), Village-Dhureri, Tehsil- Depalpur, District-Indore (MP) 3.00 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 14/06/23 को परियोजना प्रस्तावक उमा दुवे ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री विजय मिश्रा, जियोग्रीन इन्वायरो हाऊस प्रा.लि.लखनऊ उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 54 दिनांक 12/01/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर दिशा में 31 मीटर पर पक्का रोड़ है, इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुत करे तथा खदान क्षेत्र खुदा हुआ परिलक्षित हो रहा है, प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत की एनओसी नहीं है, अतः परियोजना प्रस्तावक ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-81 के सरल क्रमांक-71 पर दर्ज है।

652वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 जून 2023

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. खदान के उत्तर दिशा में 31 मीटर पर पक्का रोड़ है, इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुत करे
2. प्रश्नाधीन खदान का कुछ भाग आंशिक रूप से खुदा है इस संबंध में जिला खनिज अधिकारी से स्पष्ट अभिमत ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करे ।
3. प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत की एनओसी नहीं है, अतः परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति शर्तों में माइनिंग प्लान के अनुरूप कितनी मात्रा का खनन कार्य होना था, कितना खनन कार्य हुआ, कितनी गहराई तक खनन कार्य हुआ है तथा यह भी स्पष्ट करेंगे कि खनन कार्य माइनिंग प्लान के अनुरूप हुआ है कि नहीं, यदि नहीं हुआ है तो माइनिंग प्लान के किन-किन बिन्दुओं का उल्लंघन हुआ है इन तथ्यों को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
5. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

17. Case No 9940/2023 Shri Balveer Parmar, R/o Krishna Dham Colony, Depalpur, District-Indore (MP)- 453115, Prior Environment Clearance for Sagdod Stone Mining in an area of 4.00 ha. (10070 cum per annum) (Khasra No. 843/2/2, 843/1/3, 843/2/1), Village- Sagdod, Tehsil- Depalpur, District-Indore (MP)

This is case of Stone Mining. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 843/2/2, 843/1/3, 843/2/1), Village- Sagdod, Tehsil- Depalpur, District-Indore (MP) 4.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 14/06/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री बलबीर परमार (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री विजय मिश्रा, जियोग्रीन इंवायरो हाऊस प्रा.लि.लखनऊ उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 146

652वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 जून 2023

दिनांक 20/01/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड की गई गूगल इमेज में खदान का रकबा 0.1 हे. दर्शाया गया है जबकि अन्य दस्तावेज अनुसार खदान क्षेत्र का रकबा 4.0 हे. उल्लेखित है। अतः समिति चर्चा उपरांत परियोजना प्रस्तावक को निदेशित किया कि उपरोक्त स्थिति को स्पष्ट करते हुए परिवेश पोर्टल पर गूगल इमेज में खदान का वास्तविक रकबा उल्लेख करते हुए परिवेश पोर्टल पर अपलोड करे।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चा:-

संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला- सिंगरौली (रेत खनिज)

जिला खनिज अधिकारी, सिंगरौली ने पत्र क्र०. 2135/खनिज/रेत/डी.एस.आर./2023 सिंगरौली दिनांक 14/06/2023 के द्वारा जिले की संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) सेक में प्रेषित की है। आज दिनांक 14/06/2023 को प्रभारी खनिज अधिकारी श्री ए.के. राय के द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रभारी जिला खनिज अधिकारी द्वारा बताया गया कि संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को जिले की गठित समिति द्वारा संशोधित /अनुमोदित की जाकर 21 दिवस हेतु दिनांक 13/06/23 से जिला पोर्टल पर आमजन के दावों /आपत्ति हेतु अपलोड किया गया है तथा पोर्टल पर आमजन के दावों आपत्ति हेतु जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को प्रदर्शित करने के दौरान उक्त अवधि में कोई दावा आपत्ति प्राप्त होती है तो उसके निराकरण उपरांत उन्हे नवीन संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुये अद्यतन रिपोर्ट पुनः प्रस्तुत की जावेगी। प्रभारी जिला खनिज अधिकारी द्वारा बताया गया कि म.प्र. शासन खनिज साधन विभाग के मंशा अनुरूप सिंगरौली जिले की रेत खदानों के समूह का गठन मौका निरीक्षण किया जाकर नये सिरे से किया गया जिससे रेत खदानों के 61 स्थानों के अतिरिक्त 01 नवीन रेत खदान ग्राम -तलवा तह०. - देवसर, खसरा क्र०. 118 रकबा 03 हेक्टे. क्षेत्र को भी नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल किया गया है। प्रभारी खनिज अधिकारी ने बताया कि पूर्व में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दर्ज खदानें एवं नीलामी हेतु प्रस्तावित खदानों में से जिन खदानों के क्वार्टिनेट, खसरा क्रमांक, रकबा एवं खदान क्षेत्र की गहराई आदि में परिवर्तन हुआ है उसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार दिया गया है:-

1. कटौली-1, कटौली-2, खजुरी, बसौड़ा-1, बसौड़ा-3, नौढ़िया, नौढ़िया-2, चांचर, चांचर-2, जरहा, हरहवा-1, हरहवा-3, पिपराकुरन्द-1, पिपराकुरन्द-2, ओरगाई-1, ओरगाई-2, रेही, खमरियाकला,

652वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 जून 2023

तिनगुडी, जियावन, कारी, मजौना, चकुआर, जगहत, ढोंगा, निगरी, हर्दी, भरसेंडी, भुडकुड-1, भुडकुड-2, रजमिलान, रजमिलान-2, रैला, रैला-2, कोयलखूथ, रम्पा, अमिलवान, कर्सुआराजा कुल 38 खदानों के आक्षांश एवं देशांश में परिवर्तन हुए हैं। जो डी.एस.आर. के टेबिल नं. 4 पर अंकित हैं।

2. रेत खदान तलवा खसरा क्रमांक 118 रकवा 3.00 हे. नवीन खदान सामिल की गई है जो डी.एस.आर. के टेबिल 28 के बिन्दु क्रमांक 62 पर अंकित हैं।
3. रेत खदान कटौली-2 खसरा क्रमांक 2490 रकवा 6.00 हे. के स्थान पर परिवर्तित रकवा 3.00 हे. किया गया है, तथा खनन योग्य मात्रा 72000 घन मी. के स्थान पर परिवर्तित मात्रा 36000 घन मी. किया गया है। यह खदान टेबिल नंबर 28 के बिंदु क्रमांक 53 पर अंकित हैं।
4. रेत खदान बसौडा-1 पूर्व डी.एस.आर. में मात्रा 35000 घन मी. थी (43.75%) जो नवीन संसोधित डी.एस.आर. में 48000 घन मी. की गई है (60%)। यह खदान टेबिल नंबर 28 के बिंदु क्रमांक 1 पर अंकित हैं।
5. रेत खदान चांचर-2 पूर्व डी.एस.आर. में खसरा क्रमांक 43 रकवा 3.20 हे. था एवं खनन योग्य मात्रा 38400 घन मी. अंकित था नवीन डी.एस.आर. में खसरा क्रमांक 1 रकवा 2.00 हे. खनन योग्य मात्रा 24000 घन मी. है। यह खदान टेबिल नंबर 28 के बिंदु क्रमांक 46 पर अंकित हैं।
6. रेत खदान जरहा का पूर्व डी.एस.आर. में रकवा 2.262 हे. एवं खनन योग्य मात्रा 27144 घन मी. थी जो वर्तमान नवीन संसोधित डी.एस.आर. में रकवा 2.00 हे. तथा खनन योग्य मात्रा 24000 घन मी. किया गया है। यह खदान टेबिल नंबर 28 के बिंदु क्रमांक 8 पर अंकित हैं।
7. रेत खदान औरगाई-1 का पूर्व डी.एस.आर. में खनन योग्य मात्रा 50000 घन मी. (50%) थी जो वर्तमान नवीन संसोधित डी.एस.आर. में खनन योग्य मात्रा 72000 घन मी. (60%) किया गया है। यह खदान टेबिल नंबर 28 के बिंदु क्रमांक 35 पर अंकित हैं।
8. रेत खदान औरगाई-2 का पूर्व डी.एस.आर. में खनन योग्य मात्रा 50000 घन मी. (50%) थी जो वर्तमान नवीन संसोधित डी.एस.आर. में खनन योग्य मात्रा 72000 घन मी. (60%) किया गया है। यह खदान टेबिल नंबर 28 के बिंदु क्रमांक 36 पर अंकित हैं।
9. रेत खदान तिनगुडी का पूर्व डी.एस.आर. में रकवा 2.00 हे. एवं खनन योग्य मात्रा 36000 घन मी. थी जो वर्तमान नवीन संसोधित डी.एस.आर. में रकवा 1.00 हे. तथा खनन योग्य मात्रा 18000 घन मी. किया गया है। यह खदान टेबिल नंबर 28 के बिंदु क्रमांक 18 पर अंकित हैं।
10. रेत खदान जियावन का पूर्व डी.एस.आर. में खसरा क्रमांक 555 था जिसका नवीन खसरा क्रमांक 1 हो गया है यह खदान टेबिल नंबर 28 के बिंदु क्रमांक 9 पर अंकित हैं।
11. रेत खदान ढोंगा का पूर्व डी.एस.आर. में रकवा 5.50 हे. तथा खनन योग्य मात्रा 66000 थी जो **Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020** के प्रावधानों अनुसार प्रतिबंधित दूरी छोड़ने पर रकवा 1.50 हे. क्षेत्र तथा खनन योग्य 18000 उपलब्ध होता है जिसे नवीन संसोधित डी.एस.आर. में टेबिल नंबर 28 के बिंदु क्रमांक 43 पर अंकित किया गया है।
12. रेत खदान रजमिलान का पूर्व रकवा 4.90 हे. एवं खनन योग्य मात्रा 58800 घन मी. थी जो वर्तमान नवीन संसोधित डी.एस.आर. में रकवा 2.50 हे. तथा खनन योग्य मात्रा 30000 घन मी. किया गया है। यह खदान टेबिल नंबर 28 के बिंदु क्रमांक 17 पर अंकित हैं।

652वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 14 जून 2023

13. रेत खदान रैला-2 का पूर्व रकवा 4.00 हे. एवं खनन योग्य मात्रा 48000 घन मी. थी जो वर्तमान नवीन संसोधित डी.एस.आर में रकवा 2.00 हे. तथा खनन योग्य मात्रा 24000 घन मी. किया गया है। यह खदान टेबिल नंबर 28 के बिंदु क्रमांक 58 पर अंकित है।
14. रेत खदान कोयलखूथ का पूर्व रकवा 2.16 हे. एवं खनन योग्य मात्रा 25920 घन मी. थी जो वर्तमान नवीन संसोधित डी.एस.आर में रकवा 2.00 हे. तथा खनन योग्य मात्रा 24000 घन मी. किया गया है। यह खदान टेबिल नंबर 28 के बिंदु क्रमांक 14 पर अंकित है।
15. रेत खदान अमिलवान का पूर्व में खनन योग्य मात्रा 20000 घन मी. (30%) थी जो वर्तमान नवीन संसोधित डी.एस.आर में खनन योग्य मात्रा 34800 घन मी. (60%) किया गया है। यह खदान टेबिल नंबर 28 के बिंदु क्रमांक 19 पर अंकित है।
16. रेत खदान कर्सुआराजा का पूर्व रकवा 3.00 हे. एवं खनन योग्य मात्रा 35000 घन मी. थी जो वर्तमान नवीन संसोधित डी.एस.आर में रकवा 1.00 हे. तथा खनन योग्य मात्रा 18000 घन मी. किया गया है। यह खदान टेबिल नंबर 28 के बिंदु क्रमांक 12 पर अंकित है।
17. इस प्रकार 02 खदानों में खसरा परिवर्तन, 09 खदानों में रकवा में परिवर्तन तथा 13 खदानों में खनन योग्य मात्रा एवं 38 खदानों के अक्षांश एवं देशांश में परिवर्तन किया गया है। तथा 01 नवीन खदान सामिल की गई है।

अतः समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशांसाओ के साथ **सिंगरौली** जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण की ओर प्रेषित किया जाये।

चंद्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

652वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 जून 2023

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

652वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 14 जून 2023

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

652वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 जून 2023

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- ‘B’

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.

652वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 14 जून 2023

16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - l. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.

652वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 14 जून 2023

- vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.

652वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 14 जून 2023

10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.
 - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - r. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work

652वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 14 जून 2023

permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.

652वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 14 जून 2023

10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).

652वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 14 जून 2023

31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The undertaking inter alia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carried out in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and discussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three years and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
 - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.

652वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 14 जून 2023

38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मल्टिचिंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिंग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जायें ।
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चैनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बेरियर जोन/नॉन माइनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियों आने पर, पौधों के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना ।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है ।

नोट – 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधों जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास प्रजातियाँ ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियों, खस घास अगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीट
3	चौथी से पाँचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर